साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 23-29 जनवरी , 2023, वर्ष-8, अंक-41

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले-गरीब का कल्याण प्राथमिकता: शिवराज ने सिंगरौली को दी सौगातें, हितग्राहियों को भूखंड आवंटित

रीवा संभाग के सात लाख किसानों के खाते में सीएम ने डाले 140 करोड़

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली पहुंचे। दोनों ने सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में जिले की पंचायत क्षेत्रों के 25 हजार 412 हितग्राहियों को भूखंड आवंटित किए। मुख्यमंत्री सिंगरौली जिले के लिए अनेक सौगातों की घोषणा की। योजना में गरीब परिवारों, जिनके पास स्वयं की भूमि भी नहीं है, शासन द्वारा 60 वर्ग मीटर का नि:शुल्क भू-खंड आवंटित किया जाएगा। जिले में 421 एकड़ रकबे में हितग्राहियों को नि:शुल्क भू-खंड आवंटित किए। शिवराज ने सीएम किसान कल्याण योजना में सिंगरौली से सिंगरौली, सीधी-सतना और रीवा जिले के 6,78,408 किसानों के खातों में 135 करोड़ 68 लाख रुपए अंतरित किए।

किसानों को सरकार दे रही दस हजार

सीएम ने कहा कि कमलनाथ फिर बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया। जब डेढ़ साल के लिए इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार किसानों के खाते में 10 हजार रुपए डाल रही है। सीएम ने कहा कि हम बैगा आदिवासी महिलाओं को 1000 रुपए सालाना सहायता राशि देंगे।

मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 248 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सिंगरौली शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 60 करोड़ 30 लाख की लागत से बनने वाले माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज और 33 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल हिर्रवाह (बैढ़न) और 31 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल चकरिया का शिलान्यास भी किया।

सरसों की साग, चने की भाजी भी खाई

मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरसों की साग, चने की भाजी, मकाई की रोटी और दाल का भूखंड वितरण के दौरान हितग्राहियों के साथ आनंद लिया। राजनाथ सिंह इस दौरान मुख्यमंत्री और सरकार की सराहना करते रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इतना मीठा भोजन दिल्ली में कहां मिलेगा।

प्राइवेट कराने पर 50 रुपए लगेगी फीस

गेहूं बेचने के लिए एक फरवरी से रजिस्ट्रेशन

भोपाल। मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। किसान 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। किसान किस सेंटर पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, किस तारीख को उपज लेकर जाएंगे, यह तय करने की सुविधा किसानों को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कियोस्क, लोक सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी शासन ने तय कर दी है। 50 रुपए फीस इसके लिए तय की गई है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और प्राइवेट साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। यहां किसानों को प्रति रजिस्ट्रेशन की फीस 50 रुपए चुकाना होगी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों एवं विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और एमपी किसान एप पर नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन होंगे।

पहले और अब यह है प्रोसेस

पहले किसान को फसल बेचने के लिए मोबाइल पर एसएमएस मिलता था। जिसमें तारीख लिखी होती थी, उसी दिन किसान गेहूं लेकर सेंटर पर जा सकते थे। इससे कई बार किसान परेशान भी होते थे। नई व्यवस्था में किसान खुद ही दिन, टाइम और सेंटर तय कर सकेंगे।

सीएम शिवराज सिंह ने अध्यक्षों से बात कर किया ऐलान

जिपं अध्यक्षों का वेतन अब एक लाख और राज्य मंत्री का दर्जा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 54 हजार से बढ़कर एक लाख रुपए होगा। मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्षों के संघ के कार्यक्रम को समत्व भवन में संबोधित किया। यहां पर सीएम ने ऐलान किया कि राज्य शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। पद के अनुसार प्रोटोकॉल के विधिवत पालन के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय और वाहन भत्ता आदि की राशि को बढ़ा कर एक लाख रुपए किया जाएगा। राष्ट्रीय पर्वों पर जहां मंत्री नहीं जाएंगे वहां जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

विकास को मिलेगी गति

सीएम ने कहा कि 5 फरवरी से प्रदेश में आरंभ हो रही विकास यात्रा, राज्य के नव निर्माण और विकास को नई गति तथा विश्वास प्रदान करेगी। जिला पंचायत अध्यक्षों सहित सभी पंचायत प्रतिनिधि विकास और जन-कल्याण के इस अभियान में सहभागी हैं। हम प्रदेश की प्रगति और जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष जन-कल्याण के इस अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

हर तीन माह में करेंगे संवाद

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-कल्याण की योजनाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जिला पंचायत अध्यक्ष सशक्त माध्यम हैं। वे प्रदेश में विकास के कार्यों को भागीरथ बन कर आगे आएं। विकास कार्यों तथा जन-कल्याण की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जनपद अध्यक्ष तथा सरपंच के मध्य परस्पर समन्वय आवश्यक है। राज्य में पंचायत राज संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

जिपं अध्यक्षों की मांग

- जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा, अत: राज्य मंत्री स्तर का प्रोटोकाल दिया जाए, कलेक्टर उसका पालन करें।
- पहले की तरह जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली में मतांकन का अधिकार दिया जाए।
- जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों में पदस्थ तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण से पहले जिला पंचायत अध्यक्षों से स्वीकृति ली जाए।
- जिला पंचायत अध्यक्षों का वेतन और वाहन भत्ता मिलाकर अभी 54,100 रुपए है, जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपए प्रतिमाह किया जाए।
- जिला पंचायत अध्यक्षों को स्वेच्छा विकास निधि 25 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र के मान से दी जाए।
- पंचायत राज अधिनियम 1994 को पुन- यथावत लागू किया जाए।
- जिला पंचायत अध्यक्षों को सांसद-विधायक की भांति परिचय पत्र जारी किए जाएं।
- जिला पंचायत और मनरेगा के तहत होने वाले सभी निर्माण कार्यों के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों से अनुमोदन लिया जाए।
- राष्ट्रीय पर्वों पर जिस जिले में मंत्रीगण नहीं पहुंच पाते, वहां जिला पंचायत अध्यक्षों से ध्वजारोहण कराया जाए।
- जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला योजना समिति में पदेन सदस्य घोषित किया जाए।
- 11- गौण खनिज की राशि से स्वीकृत होने वाले विकास कार्यों की समिति में जिला पंचायत अध्यक्षों को शामिल किया जाए।
- 12- जिला पंचायतों को 15वें वित्त व अन्य मदों में जो राशि स्वीकृति की जाती है, उसमें कम से कम तीन गुना वृद्धि की जाए।

पंचायतों में पता चलेगी प्रकरण की स्थिति

ग्राम पंचायतों में शुरू होगी ई-कोर्ट की सुविधा

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वालों को कोर्ट का बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द ही ई-पंचायतों में ई-सेवा केंद्र की सुविधाएं भी शुरू होगी। इस केंद्र पर याचिकाकर्ता को ई-कोर्ट के तहत मिलने वाली डिजिटल सुविधाओं में सहूलियत मिलेगी। इस व्यवस्था के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर सचिव व ग्राम रोजगार सहायकों को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रारंभिक चरण में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय परिसर में प्रायोगिक आधार पर ई-सेवा केंद्र बनाए गए हैं। प्रयोग सफल होने के बाद इस केंद्र के तहत पंचायत स्तर पर ही याचिकाकर्ता को सुविधाएं मिल सकें। जल्द ही सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। इस योजना के तहत प्रदेशभर में चयनित पंचायतों में भी चरणवार ई-कोर्ट व्यवस्था शुरू होगी।

याचिकाकर्ता को मिलेंगी ये सुविधाएं

ई-सेवा केंद्रों पर याचिकाकर्ता को वाद की स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख समेत अन्य विवरण की पूछताछ, प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन को सुगम बनाना, याचिकाओं की ई-फाइलिंग बनाने के लिए याचिकाकर्ता को हार्ड कॉपी की स्कैनिंग से लेकर ई-सिग्नेचर जोड़ना, सीआईएस में उनको अपलोड करना, दायरा संख्या उत्पन्न करना। ई-भुगतान, ई-स्टांप पेपर की ऑनलाइन खरीद में सहायता करना। आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर, सहायता प्राप्त करना। एंड्राइड व आइओएस के लिए ई-कोर्ट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने समेत अन्य सहूलियत मिलेगी।

मिलेट किसान सम्मेलन तथा प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर बोले केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल

भावी पीढ़ियों को जीवन देने पारंपरिक खेती आवश्यक

मंडला। तैय्यद जावेद अली

2 दिवसीय मिलेट किसान सम्मेलन तथा प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग एवं जल शक्ति राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जनजातियों द्वारा की जाने वाली पारंपरिक खेती जल, मृदा एवं पर्यावरण को संरक्षित करती है, किन्तु पश्चिमी देशों की नकल कर खाद एवं ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक खेती के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। देश को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाने तथा भावी पीढ़ियों को जीवनदान देने के लिए पारंपरिक खेती आवश्यक है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मंडला-डिंडौरी जिले में कोदो-कुटकी का बहुत उत्पादन होता है, जिनमें पानी कम लगता है, खाद आदि की आवश्यकता नहीं होती है, इन उपजों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है किन्तु इन मोटे अनाजों के खिलाफ बात करके जनमानस को भ्रमित किया गया और ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया गया जो न केवल पानी और खाद अधिक मांगती हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं जिनके प्रबंधन पर खर्च भी अधिक होता है। श्री पटेल ने कहा कि इन गलतियों को सुधारते हुए परंपरागत खेती की ओर वापिस आने का अवसर है। वर्तमान सरकारें पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं।

इस अवसर पर विधायक मंडला देवसिंह सैयाम ने किसानों से परंपरागत खेती से जुड़ने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि किसान इस सम्मेलन में बताई गई तकनीकियों को समझें तथा खेती में उनका उपयोग करें। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास कर रही है। खेती के साथ-साथ प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में डायरेक्टर मिली दुबे ने आयोजन के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के मंच पर मोटे अनाज का प्रस्ताव रखकर सराहनीय पहल की है। समूचे विश्व में मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता पहली बार भारत को मिली है जिसकी बैठकें विभिन्न शहरों में हो रही हैं, इन बैठकों में मोटे अनाज का नाश्ता कराया जा रहा है जिसकी शुरूआत इंदौर से की जा चुकी है। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग एवं जल शक्ति राज्यमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज की प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मंडला जिले में अच्छी मात्रा में कोदो-कुटकी की फसल होती है किन्तु उनकी प्रोसेसिंग के लिए अभी नाममात्र की इकाईयाँ हैं। शासन द्वारा अनेकों योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, किसानों को चाहिए कि वे इन योजनाओं से जुड़कर प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तथा अपने उत्पादों से अधिक लाभ कमाएँ। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज से विदेशियों के स्वाद के अनुरूप उत्पाद बनाएं।

बढ़ती आबादी पानी और भोजन के लिए चुनौती

श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आबादी का बढ़ता घनत्व पानी और भोजन के लिए चुनौती है। घटता जल स्तर तथा भूमि की उत्पादन क्षमता का कम होना चिंताजनक है। ज्यादा पानी की फसलों को स्वीकार करना चूक थी। अब ऐसी फसलों का चयन आवश्यक है जिनमें खाद और पानी की जरूरत कम पड़े। पानी की एक-एक बूंद का सदुपयोग आवश्यक है। यदि समय रहते इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए पानी और भोजन की उपलब्धता कठिन होगी।

योग और आयुर्वेद को दुनिया ने स्वीकारा -

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग एवं जल शक्ति राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 21वी सदी भारत की होगी, स्वामी विवेकानंद की यह भविष्यवाणी अब सच साबित हो रही है। स्वस्थ रहने के लिए पूरे विश्व में योग को आत्मसात किया गया है। कोरोनाकाल में योग तथा आयुर्वेद की दवाईयों ने चमत्कारिक परिणाम दिए हैं। इस अवसर पर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग एवं जल शक्ति राज्यमंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किसान उन्नति एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया तथा ज्ञानपुस्तिका एवं मिलेट कलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम के अंत में हितग्राहियों को शासन की महत्वपूर्ण योजना पीएमएफएमई के तहत हितलाभ वितरित किए गए।

ये रहे उपस्थितः कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक मंडला देवसिंह सैयाम, विधायक निवास डॉ. अशोक मर्सकोले, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उईके, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, अध्यक्ष जनपद पंचायत मवई मनीषा मरकाम, अध्यक्ष जनपद पंचायत मंडला सोनू भलावी, जिला पंचायत सदस्य शैलेष मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा, भीष्म द्विवेदी, प्रफुल्ल मिश्रा, अपर कलेक्टर मीना मसराम, संयुक्त संचालक कृषि केएस नेताम, उपसंचालक कृषि मधुअली सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

सरकार ने बदली तारीखः अब 5 फरवरी से होगी मप्र में विकास यात्रा

सीएम शिवराज की दो टूक-सभी मंत्री करें गांवों का दौरा

मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में होंगे हितग्राही सम्मेलन

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में विकास यात्रा अब एक फरवरी की जगह पांच फरवरी को संत रविदास जयंती से प्रारंभ होगी। यह 20 फरवरी तक चलेगी और इसे प्रभारी मंत्री आवश्यकता अनुसार पांच दिन यानी 25 फरवरी तक बढ़ा सकेंगे। इसमें विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में हितग्राही सम्मेलन होंगे। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में विभिन्न योजनाओं के चिन्हित हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा की कार्ययोजना को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में बताई।

तैयारी कर लें

सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे यात्रा प्रारंभ होने से पहले दो दिन का दौरा करके तैयारी कर लें। मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि विकास की गतिविधियों और जन कल्याणकारी कामों का लाभ जनता को समय सीमा में बिना किसी बाधा के मिलना चाहिए।

शिलान्यास मंत्री करेंगे| विकास यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों के सम्मेलन किए जाएं। इसमें मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में चिन्हित हितग्राहियों को लाभ वितरण के साथ उनसे चर्चा कर योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाए। साथ ही जो काम पूरे हो चुके हैं, उनका लोकार्पण और प्रस्तावित कार्यों का शिलान्यास प्रभारी मंत्री करेंगे।

निरीक्षण भी होगा

मंत्रियों के जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालयों पर दौरे होंगे। यात्रा के दौरान जन संवाद के साथ शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों, आंगनबाड़ी, विद्युत और पेयजल व्यवस्था, जल जीवन मिशन के कामों का निरीक्षण भी होगा।

जन उत्सव

यात्रा मार्ग का निर्धारण कलेक्टर प्रभारी मंत्री से चर्चा करके करेंगे। बैठक में कमिश्नर-कलेक्टर वर्जुअली जुड़े थे। जन उत्सव के रूप में मनाया जाए गणतंत्र दिवस मुख्यमंत्री ने बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसे जन उत्सव के रूप में मनाया जाए।

जागत गांव हमार

नौ महीने बाद भी मंत्री-मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई पूरी

दाल-सोया और कपास उद्योग पर मंडी टैक्स की मार

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश सरकार की घोषणाएं अधूरी रहने से उद्योगों का भरोसा टूट रहा है। मंडी टैक्स से बेहाल प्रदेश के दाल, सोयाबीन और कपास उद्योगों के सामने मंत्री ही नहीं मुख्यमंत्री भी राहत देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐलान एक-दो नहीं, बल्कि पांच बार हुआ। हालांकि घोषणाओं का गर्भकाल नौ माह में भी पूरा नहीं हुआ।

अप्रैल में पहली घोषणा

अप्रैल में पहली घोषणा हुई थी, लेकिन कागज पर आदेश की डिलीवरी अब तक नहीं हो सकी है। सरकार के रवैये से प्रदेश के उद्योग हताश हैं। उत्पादन और कारोबार प्रभावित होता देख निराश उद्यमी पड़ोसी राज्यों में पनाह ले रहे हैं।

70 पैसे प्रति सैकड़ा

मप्र में मंडी शुल्क की दर 1.70 प्रतिशत यानी एक रुपए 70 पैसे प्रति सैकड़ा है। उद्योगों को कृषि उपज खरीदी पर यह शुल्क चुकाना होता है। दाल मिलें, कपास और सोया प्रोसेसिंग उद्योग इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

देश आत्मनिर्भर नहीं

पड़ोसी राज्यों में मंडी शुल्क की दर 0.50 से 0.80 प्रतिशत है। यानी 50 पैसे से 80 पैसे तक सीमित है। इतना ही नहीं, मप्र अपनी उपज पर नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से या विदेश से आने वाले उत्पाद पर भी मंडी टैक्स वसूलता है। दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर नहीं है।

हर मंच से की गई घोषणा

25 अप्रैल 2022: इंदौर में दाल मिल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक हुई। अतिथि कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद। उद्योगों के सामने कृषि मंत्री ने की घोषणा, मंडी शुल्क में दी जाएगी राहत।

9 अक्टूबर 2022: दि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सोपा) द्वारा इंटरनेशनल सोया कानक्लेव आयोजित। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कानक्लेव के मंच से कृषि मंत्री कमल पटेल का ऐलान, सोया उद्योग परेशान न हो, सप्ताहभर में मंडी शुल्क में राहत देने का निर्णय लेगी सरकार।

15 दिसंबर 2022: भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की भेंट। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, मंडी में दी जाएगी छूट।

17 दिसंबर 2022: दाल उद्योगों के गढ़ कटनी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने की घोषणा, दलहन पर मंडी टैक्स से राहत देगी सरकार।

प्रदेश सरकार भी वाकिफ

विदेश व अन्य प्रदेश से आयातित दलहन पर दाल मिलों को तमाम टैक्स देने के बाद दोबारा ये शुल्क प्रदेश में चुकाना होता है। मंडी शुल्क की मार से प्रदेश सरकार भी वाकिफ है। कम से कम तीन बार इंदौर में ही कृषि मंत्री कमल पटेल मंडी शुल्क में राहत देने की घोषणा कर चुके हैं। दो बार मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के सामने इसकी घोषणा की। पहली घोषणा को नौ महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकारी ढिठाई ऐसी कि आदेश आज तक जारी नहीं हुआ।

दो रुपए महंगी प्रदेश की दाल

प्रदेश में 700 दाल मिलें हैं। सबसे ज्यादा दाल मिलें इंदौर और कटनी में हैं। दोनों शहरों में 145 से 150 तक दाल मिलें इस समय चल रही हैं। दाल मिल संचालकों के अनुसार प्रदेश को दाल खरीदने के लिए चना राजस्थान से तुवर या अरहर कर्नाटक व विदेश से और अन्य दलहन भी आयात करना होता है। अन्य प्रदेशों और विदेश की उपज पर भी सरकार मंडी टैक्स लेती है।

मिलों ने उत्पादन 40 प्रतिशत घटाया

स्थानीय उपज से बनने वाली दाल की लागत मप्र प्रदेश की मिलों में अन्य प्रदेशों की तुलना में दो रुपए क्विंटल बढ़ जाती है, जबकि अन्य राज्य और विदेश से आयातित दलहन से दालों की लागत इससे भी ज्यादा महंगी होती है। इसका असर ये होता है प्रदेश की दालें महंगी होने के कारण बाहर के बाजार में प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पातीं। महाराष्ट्र, गुजरात और आसपास की मिलें अपनी दाल मप्र के बाजार में बेचती हैं। बड़े टैक्स का असर है कि मिलों ने उत्पादन 40 प्रतिशत तक घटा दिया है।

मोघे ने लिखा था सीएम को पत्र

मंडी टैक्स से परेशान निमाड़ की कपास मिलों ने 11 अक्टूबर से काम बंद कर दिया था। समर्थन में भाजपा के पूर्व सांसद कृष्णमुरारी मोघे भी उतरे। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख मंडी टैक्स में राहत देने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था रुई की एक गांठ बनाने में गुजरात और महाराष्ट्र में 100 रुपये टैक्स का भार आता है। मप्र में 600 रुपये टैक्स का भार आता है। प्रतिस्पर्धा में यहां के उद्योग पिछड़ रहे हैं। 200 जिनिंग फैक्ट्रियां गुजरात या महाराष्ट्र में शिफ्ट हो चुकी हैं।

दाल उद्योग शुल्क माफी नहीं मांग रहा, बल्कि अन्य प्रदेशों के समान टैक्स को युक्तियुक्त करने की मांग की। 2019 तक राहत मिलती थी। हैरानी है कि मंत्री की घोषणा के नौ महीने बाद भी आदेश नहीं हुआ। हर दाल मिल कम से कम 50 लोगों को सीधे रोजगार देती है। मिलें उत्पादन घटा रही हैं। कुछ महाराष्ट्र, गुजरात की सीमा पर जा रही हैं।
-सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष आल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन

सोया उद्योगों ने समस्या बताई थी तो कृषि मंत्री ने कानक्लेव के मंच से मंडी शुल्क में राहत देने का ऐलान किया था। आदेश आज तक जारी नहीं हुआ। मप्र सोया प्रदेश कहा जाता है, लेकिन सोया उद्योग भारी करों का सामना कर रहा है। हमारे यहां उत्पादन लागत बढ़ रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्य के उद्योगों को इसका लाभ मिल रहा है।
-डीएन पाठक, कार्यकारी निदेशक, दि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया

मोटे अनाजों की वापसी, एक साल में 129 प्रतिशत बढ़ी मांग

संजय माकवे
वरिष्ठ पत्रकार

पिछले कुछ दशकों में गेंहू, चावल की कृषि ने मोटे अनाजों यथा मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी आदि को हमारी कृषि और थाली से लगभग बाहर कर दिया है। कृषकों और उपभोक्ताओं की मोटे अनाज (मीलेट्स) को भूलने की प्रवृत्ति ने हमारे देश के कृषकों की आय नागरिकों के स्वास्थ्य इंडेक्स दोनों को ही दुष्प्रभावित किया है। किंतु अब मिलेट्स के दिन फिर बहुरने लगे हैं। इनकी मांग पिछले एक साल के दौरान ही 129 प्रतिशत बढ़ चुकी है। खपत बढ़ने से किसानों ने खेती का रकबा भी 116 प्रतिशत बढ़ाया है। भारतीय कृषक मिलेट्स की कृषि में तकनीकी व प्राकृतिक उपायों के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में सफल हुए।

विगत पांच वर्षों में मोटे अनाज का बाजार पांच गुना हो चुका है। मोटे अनाज अपने स्वाद, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ सात: कैल्शियम आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जस्ता, पोटेशियम, विटामिन बी-6 और विटामिन बी-3 के प्रबल वाहक भी होते हैं। इन दिनों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान जैसे जनजातीय बहुल प्रदेशों में तो जनजातीय बंधुओं द्वारा प्राकृतिक कृषि से उपजाएं जाने वाले मोटे देशज अनाजों की मांग महानगरों से व विदेशों से भी आने लगी है। जनजातीय क्षेत्रों में उगने वाले ये कोदो, कुटकी आदि अनाज कई बीमारियों के निदान का प्रतीक बन गए हैं। ये जनजातीय मिलेट्स महानगरों और विदेशों में सैकड़ों रूपये किलो तक हाथो हाथ लिए जाते हैं। जहां देश के बड़े वर्ग ने अपनी थाली में स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों को स्थान देना प्रारंभ किया है वहीं विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, बायोडीजल हेतु व एथेनाल हेतु भी मोटे अनाजों की खपत बड़ी मात्रा में होने लगी है। खपत बढ़ने के कारण मोटे अनाज के बाजार भाव भी आकर्षक व लाभकारी मिलने लगे हैं।

आज भारत विश्व मिलेट (मोटे अनाज) के उत्पादन में विश्व भर में सर्वाधिक अग्रणी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखण्ड, तमिलनाडु, और तेलगांना आदि प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक राज्य हैं। आसाम और बिहार में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों की खपत होती है। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का स्थान आता है। जनजातीय समाज के बंधू कोदों, कुटकी, सावां आदि की खेती की कृषि परंपरागत रूप से प्राकृतिक रीति नीति से सैकड़ों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। जनजातीय बंधुओं द्वारा उत्पादित ये मोटे अनाज बड़े ही स्वास्थ्य वर्द्धक व आयुष वर्द्धक होते हैं। इन मोटे अनाजों की फसल का एक विशेष गुण होता है कि इनकी कृषि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी बड़ी जीवट होती हैं। सूखा, अधिक तापमान, कम पानी की भूमि, कम उपजाऊ जमीन आदि आदि की परिस्थिति में भी इनका अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। मोटे अनाज की कृषि को गरीब किसान की कृषि इसलिए ही कहा जाता रहा है। मोटे अनाजों की इस जिजीविषा पूर्ण कृषि, उत्पादन अनुपात, लागत अनुपात, पौष्टिकता, बहु उपयोगिता और पर्यावरण मित्र स्वभाव के कारण इन फसलों को सुपर फूड कहा जाने लगा है। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि पारंपरिक भारतीय अनाजों में स्वास्थ्य का खजाना छुपा है। यही कारण है कि बीते वर्षों

में में मोटे अनाजों की बुवाई का क्षेत्रफल सतत बढ़ता ही जा रहा है और फलस्वरूप मनुष्य और पशु दोनों के उदरपोषण में मोटे अनाजों का समावेश बड़े स्तर पर बड़े प्रतिशत के साथ हो गया है।

वर्ष 2018 को भारत में ईयर ऑफ मिलेट्स् के रूप में मनाया गया था। अब इस स्थिति में एक और गुणात्मक परिवर्तन आ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफमिलेट्स् के रूप में मनाने का निर्णय किया है। वर्ष 2023 में देश भर में कृषकों को इन अनाजों के सन्दर्भ में हजारों कार्यशालाओं व अन्य माध्यमों से मोटे अनाज की प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में समझाया जाएगा। आगामी वर्ष में मोटे अनाजों के प्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के विषय में देश के नागरिकों में जागरण अभियान भी चलाया जायेगा। मोटे अनाज कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उपज दे सकते हैं और तुलनात्मक रूप से इनकों कीटनाशकों की उतनी जरूरत नहीं होती है। मोटे अनाजों को अधिक पानी-सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिक तापमान में भी आसानी से पैदा किये जा सकते हैं। यह फसलें किसानों के लिए अच्छी हैं, क्योंकि उनकी खेती करना दूसरी फसलों की तुलना में आसान है। यह कीट पंतगों से होने वाले रोगों से भी बचे रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट उत्पादन करने वालों में भारत, नाइजीरिया और चीन प्रमुख देश हैं जो कि दुनियां का 55 फीसदी उत्पादन करते हैं। देश में राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करने वाला राज्य है जहां 7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में छोटे मोटे अनाज की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में खेती की जाती है। जिसमें मध्य प्रदेश 32.4, छत्तीसगढ़ 19.5, उत्तराखण्ड 8, महाराष्ट्र 7.8, गुजरात 5.3 और तमिलनाडु 3.9 फीसदी क्षेत्रफल में छोटी मिलेट फसलों की खेती की जाती है। देश में की जाने वाली ज्वार की खेती का 50 फीसदी रकबा अकेले महाराष्ट्र से आता है। कनाड्टक में सबसे ज्यादा रागी की खेती की जाती है। सामान्यत: मोटे अनाजों की सभी फसलों की कीमत सामान्य धान से अधिक ही रहती है। रागी में पोटेशियम एवं कैल्शियम अन्य मिलेट फसलों की तुलना में ज्यादा है। कोदों में प्रोटीन 11, हल्की वसा 4.2, बहुत ज्यादा फाइबर 14.3 फीसदी के अलावा विटामिन-बी, नाइसिन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम मैगनीशियम, जिंक आदि महत्वपूर्ण पौषक तत्व पाये जाते हैं। इसी प्रकार से बाजरा में प्रोटीन, फाइबर, मैगनीशियम, आयरन एवं कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाजरा मधुमेह को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रोल के स्तर को नियंत्रित करता है। मोटे अनाज कैल्शियम, आयरन और जिंक की कमी को दूर करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मोटे अनाज गेंहू के ठीक विपरीत ग्लूटेन फ्री होते हैं और इस कारण मनुष्य को मोटापे से बचाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हरित क्रान्ति के कारण जैसे-जैसे गेहूं और धान की पैदावार बढ़ी वैसे-वैसे भारतीय थालियों से मोटे अनाज गायब हुए और पौष्टिकता कम होते चली गई थी। अब भी हमारे देश में धान और गेंहू के सामने मोटे अनाजों का उत्पादन अब भी बहुत कम है।

दुधारू पशुओं के विषाणु जनित रोग व उनका उपचार

» डॉ. शैली नागर
» डॉ. मनोज अहिरवार
-नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

दुधारू पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियां होती है। सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, अंत: व ब्रह्मा परजीवी, प्रोटोजोआ, कुपोषण तथा शरीर के अंदर की चयापचय क्रिया में विकार आदि प्रमुख कारणों में हैं। इन बीमारियों में बहुत सी जानलेवा बीमारियां हैं तथा कई बीमारियां पशु के उत्पादन पर कुप्रभाव डालती है। कुछ बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु को लग जाती है जैसे मुह व खुर की बीमारी, गल घोंटू, आदि, छूतदार रोग कहते हैं। कुछ बीमारियां पशुओं से मनुष्यों में भी आ जाती है जैसे रेबीज (हल्क जाना), क्षय रोग आदि, इन्हें जुनोटिक रोग कहते हैं। अत: पशु पालक को प्रमुख बीमारियों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है, ताकि वह उचित समय पर उचित कदम उठा कर अपना आर्थिक हानि से बचाव तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा में भी सहयोग कर सके।

दुधारू पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियां होती है। सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, अंत: व ब्रह्मा परजीवी, प्रोटोजोआ, कुपोषण तथा शरीर के अंदर की चयापचय (मेटाबोलिज्म) क्रिया में विकार आदि प्रमुख कारणों में हैं। दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग् निम्नलिखित है।

जीवाणु जनित रोग

1. गलघोंटू रोग (एच.एस.): गाय व भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक तथा छूतदार रोग है जुकी अधिकतर बरसात के मौसम में होता है यह गोपशुओं की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। यह रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या मे पशुओं को अपनी चपेट में लेकर उनकी मौर का कारण बन जाता हैं जिससे पशु पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन, सांस लेने में तकलीफ निकालकर सांस लेना तथा सांस लेते समय तेज आवाज होना आदि शामिल है। कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के ही पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है।

उपचार तथा रोकथाम: इस रोग से ग्रस्त हुए पश को तुरन्त पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए अन्यथा पशु की मौत हो जाती है। सही समय पर उपचार दिए जाने पर रोग ग्रस्त पशु को बचाया जा सकता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगनिरोधक टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका 3 माह की आयु में दूसरा 9 माह की अवस्था में तथा इसके बाद हर साल यह टीका लगाया जाता हैं।

2.लंगड़ा बुखार (ब्लैक क्वार्टर): जीवाणुओं से फैलने वाला यह रोग गाय व भैंसों दोनों को होता है लिकिन गोपशुओं में यह बीमारी अधिक देखी जाती है तथा इससे अच्छे व स्वस्थ पशु ही ज्यादातर प्रभावित होते हैं। इस रोग में पिछली अथवा अगली टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आ जाती हैं जिससे पशु लंगड़ा कर चलने लगता है या फिर बैठ जाता है। पशु को तेज बुखार हो जाता है तथा सूजन वाले स्थान को दबाने पर कड़-कड़ की आवाज आती है।

उपचार तथा रोकथाम: रोग ग्रस्त पशु के उचार हेतु तुरन्त नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए ताकि पशु को शीघ्र उचित उपचार मिल सके। देर करने से पशु को बचना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा पैदा हुआ जहर (टोक्सीन) शरीर में पूरी को बचना लगभग असंभव हो जाता है जोकि पशु की मृत्यु का कारण बन जाता है। उपचार के लिए पशु को ऊँची डोज में प्रोकें पेनिसिलीन के टीके लगाए जाते हैं तथा सूजन वाले स्थान पर भी इसी दवा को सुई द्वारा माँस में डाला जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए पशु चिकित्सक संस्थाओं में रोग निरोधक टीके नि:शुल्क लगाए जाते हैं। पशु पालकों को सुविधा का अवश्य लाभ उठाना चाहिए।

3.ब्रूसिल्लोसिस (पशुओं का छूतदार गर्भपात): जीवाणु जनित इस रोग में गोपशुओं तथा भैंसों में गर्भवस्था के अन्तिम त्रैमास में गर्भपात हो जाता है। यह रोग पशुओं से मनुष्यों में भी आ सकाता है। मनुष्यों में यह उतार-चढ़ाव वाला बुखार (अज्युलेण्ट फीवर)नामक बीमारी पैदा करता है। पशुओं में गर्भपात से पहले योनि से अपारदर्शी पदार्थ निकलता है तथा गर्भपात के बाद पशु की जेर रुक जाती है। इसके अतिरिक्त यह जोड़ों में आर्थ्रायटिस (जोड़ों की सूजन) पैदा के सकता है।

उपचार व रोकथाम: अब तक इस रोग का कोई प्रभाव करी इस्लाज नहीं हैं। यदि क्षेत्र में इस रोग के 5प्रतिशत से अधिक पोजिटिव केस हों टो रोग की रोकथाम के लिए बच्छियों में 3-6 माह की आयु में ब्रुसेल्ला-अबोर्टस स्ट्रेन-19 के टीके लगाए जा सकते हैं। पशुओं में प्रजनन की कृत्रिम गर्भाधान पद्यति अपना कर भी इस रोग से बचा जा सकता है।

एनजीटी का निर्देश, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल किया जाए अपडेट

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अपने 17 जनवरी, 2023 को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय पर्यावरण योजनाओं को हर साल तैयार और अपडेट किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जिला पर्यावरण योजनाओं को अपडेट और लागू करने के विषय पर एनजीटी के पहले के 8 फरवरी, 2022 को दिए आदेश के क्रम में यह निर्देश पारित किया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह का प्लान तैयार करने का निर्देश सबसे पहले कोर्ट ने 15 जुलाई 2019 को जारी किया था।

इस बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी समिति द्वारा 10 अक्टूबर, 2022 को जारी रिपोर्ट में अदालत को योजनाओं की तैयारी के लिए उठाए गए कदमों और आगे की राह के बारे में जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट में जिला पर्यावरण योजना (डीईपी) को तैयार करने के संबंध में बताया गया है कि 738 में से 640 जिलों के लिए योजना तैयार कर ली गई है। वहीं 98 जिलों के लिए योजनाएं अभी तैयार की जानी हैं।

ट्रिब्यूनल ने इन रिपोर्टों को देखने के बाद संतोष व्यक्त किया है। साथ ही संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीपीसीबी की निगरानी समिति द्वारा जारी रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों और सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि जिला पर्यावरण योजनाओं में विभिन्न विषयगत विषयों पर सभी प्रासंगिक आंकड़े शामिल होने चाहिए। इसमें प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव को कवर करते हुए, पहचान की गई कमियों के साथ, उसे दूर करने की अनुमानित लागत, अपेक्षित बजटीय सहायता के साथ जरूरी कार्रवाई के लिए योजना का भी विवरण होना चाहिए।

कोर्ट ने शेष 98 जिलों के संबंध में 31 दिसंबर की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जिला योजनाओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देने की बात कही है। इसके लिए कोर्ट ने ज्यादा से ज्यादा तीन महीनों का समय दिया है। आदेश में कहा है कि सीपीसीबी को संबंधित राज्यों के साथ मिलकर इसका पालन किया जाना चाहिए। साथ ही इस कार्य योजना में कितनी प्रगति हुई इस बारे में जानकारी हर वर्ष 31 जनवरी तक वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए।

इसी तरह, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिला पर्यावरण योजनाओं या अन्य प्रासंगिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य पर्यावरण योजना को हर साल 28 फरवरी तक अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और इससे संबंधित जानकारी राज्य की वेबसाइटों पर रखी जाना चाहिए।

इसके बाद सीपीसीबी किसी अन्य मंत्रालय या प्राधिकरण के साथ मिलकर हर साल 31 मार्च तक राज्य पर्यावरण योजनाओं के आधार पर एक संयुक्त योजना तैयार करेगा और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। यह संयुक्त राष्ट्रीय योजना भी हर साल 30 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार जनरल के पास दायर की जा सकती है।

बाबूलाल दाहिया ने सतना में किसानों के लिए बीज बैंक भी बनाया

कृषि की धरोहर को संरक्षित करने का उठाया बीड़ा

पद्मश्री ने बनाया खेती के देसी यंत्र-औजार का म्यूजियम

सतना। जागत गांव हमार

पुरानी चीजों का संग्रह का शौक हर किसी को है, लेकिन कुछ जुनूनी लोग यह कर पाते हैं। कोई डाक टिकट तो कोई पुराने जमाने के सिक्के संग्रह कर रहा है। लेकिन मध्यप्रदेश का एक किसान राजाओं के म्यूजियमों से इतना प्रभावित हुआ की अपने घर में ही पुराने जमाने में खेती किसानी के काम आने वाली सामग्री, यंत्रों और औजारों का ही संग्रह कर डाला। इसका एक संग्रहालय भी बना लिया है। पद्मश्री से सम्मानित बाबूलाल दहिया इस अनोखे म्यूजियम के बारे में **जागत गांव हमार** से चर्चा के दौरान बताते हैं कि राजस्थान और हैदराबाद घूमने के दौरान वहां के म्यूजियम देखा था। वहां राजाओं- महाराजाओं की अस्त्र-शस्त्र, तलवार, ढाल यहां तक की कपड़े भी देखे। देखने के बाद सोचा कि उनकी आज उपयोगिता नहीं है फिर भी रखे हुए हैं। वहां से दिमाग में आया कि क्यों न कृषि में उपयोग की जाने वाली और चलन से बाहर हो गई सामग्रियों का एक संग्रहालय बनाया जाए और आज यह संग्रहालय बन गया।

2019 में पद्मश्री सम्मान मिला

दाहिया मध्यप्रदेश के सतना जिले में आने वाले छोटे से गांव पिथौराबाद के रहने वाले हैं। यह गांव उचेहरा-नागौद मार्ग में बसा हुआ है। जिला मुख्यालय से पिथौराबाद गांव की दूरी करीब 15 किमी है। बाबूलाल दाहिया को जैव विविधता और अनाज के देशी बीजों के संरक्षण संवर्धन को लेकर वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। कवि से किसान बने बाबूलाल के अनूठे संग्रहालय में ग्रामीण भारत की हर वो वस्तु मौजूद है और संग्रह की जा रही है जो चलन से बाहर हैं चाहे वह पत्थर के बने हों या फिर लकड़ी और लोहे के। पद्मश्री कहते हैं कि म्यूजियम में कोई चीज क्यों रखी जाती है इसलिए कि आने वाले पीढ़ी उसके बारे में जान सके कि तब कैसा चलन था। यही कारण है कि नई पीढ़ी को कृषि के चलन से बाहर हो गए उपकरणों-यंत्रों के संग्रह कर परिचय कराने का विचार आया जो अब बन कर तैयार है।

सात उद्यमियों की सामग्री का संग्रह

आधुनिक समय में गांव का किसान भी तकनीक के सहारे खेती कर मुनाफा कमा रहा है, लेकिन पुराने ग्रामीण भारत के पन्ने पलटे तो तब का किसान परंपरागत तरीके से खेती करता है। उसकी निर्भरता भी प्रकृति पर थी। तब के किसान के लिए गांव में रहने वाली सात उद्यमी लोग मददगार साबित होते थे। जैसे लोहार, बढ़ई, शिल्पकार, वंशकार, चर्मकार, कुंभकार के साथ साथ महिलाएं भी। उन्हीं सात लोगों के इर्द-गिर्द ग्रामीण भारत की कृषि चलती थी। सातों द्वारा बनाई गई चीजों का संग्रह किया गया है।

संग्रहालय में अंग्रेजों के जमाने का बाट

कवि से किसान बने बाबूलाल के अनूठे संग्रहालय में ग्रामीण भारत की हर वो वस्तु मौजूद है और संग्रह की जा रही है जो चलन से बाहर हैं चाहे वह पत्थर के बने हों या फिर लकड़ी और लोहे के। इस संग्रहालय में दशकों पुराने ताले हैं, महाराजा की ऐतिहासिक तलवार भी जो इस संग्रहालय को और भी अलग बनाती है। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने का बाट भी रखा हुआ है।

रणमत सिंह की तलवार भी रखी

संग्रहालय में कृषि आश्रित समाज की हर जरूरत की चीजें मौजूद हैं। इनकी संख्या करीब 250 है। इसके अलावा कुछ जुटाई भी जा रहीं है जो नहीं मिल रहीं हैं उनको बनवा भी रहे हैं। इसमें कई दशकों के ताले हैं जो लोहार द्वारा बनाए जाते थे। अब तो कंपनियां बनाने लगी हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रणमत सिंह की तलवार भी रखी हुई। यह तलवार मित्र अरुण पयासी ने भेंट की थी। इसके अलावा अंग्रेजों के जमाने का एक सेर का बाट भी है। एक सेर आज के एक किलोग्राम से 100 ग्राम कम होता था।

तीन कमरों में संग्रहालय पर्याप्त नहीं

दाहिया का यह अनूठा संग्रहालय गांव के ही घर में बना हुआ है। छत में ही इसके लिए कमरे तैयार कर कृषि और ग्रामीण भारत की पुरानी चलन से बाहर हो चुकी चीजें रखी हैं। वह बताते हैं कि साहित्य लेखन और शोध कार्यों की किताबें लिखी हैं। इनसे दो-तीन लाख रुपए इकठ्ठा हुए थे। और भी कुछ कवि सम्मेलनों से मिल गया। उसी बचत से यह तीन कमरे तैयार किए हैं। हालांकि यह पर्याप्त नहीं हैं दो और बन जाएं तो सपना पूरा हो जाएगा। इसके लिए सरकार से आग्रह करेंगे।

सर्जना ने एकत्रित की कृषि सामग्री

बाबूलाल दाहिया संग्रहालय में रखी वस्तुओं और सामग्री को इकट्ठा करने का श्रेय सर्जना को देते हैं। यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक संस्था है। बाबूलाल इसके संस्थापक हैं। वो बताते हैं कि इतना बड़ा काम सर्जना नामक संस्था ने किया है। इसका गठन 2002 में किया गया था। हालांकि अब मैं केवल सदस्य हूं। सुरेश दाहिया इसके अध्यक्ष हैं और बसंत तिवारी सचिव हैं।

देसी बीजों का बीज बैंक भी

जहां वर्तमान में संग्रहालय बनाया गया है वहां से 200 मीटर की दूरी पर बीज बैंक भी बनाया गया है, इसमें धान और गेहूं के देशी बीज संरक्षित कर रखे गए हैं। बचपन में देखा करते थे कि खेतों में कई तरह की धान लगी रहती थी लेकिन जब बड़े हुए तो खेतों से गायब हो गई। यहीं से देशी बीजों के संरक्षण की ललक जागी। इसका बीज बैंक हैं जहां पर 250 प्रकार के देशी अनाज के बीजों का संग्रहण है। जिसमें धान और गेहूं दोनों हैं।

अभी संग्रहालय में यह सामान रखा

बांस: चरहा टोपरा ,ओसमनिहा झउआ,गोबरहा झउआ, छन्नी टोपरिया, ढोलिया, टुकनी, ढेरइया, बंसा, घोटा,झांपी, झपलइया, दौरी,छिटबा, बेलहरा, बिजना, कुड़वारा, झलिया, झाला।

मिट्टी: हडिय़ा, तेलइया,पइना, मरका, मरकी,डहर, घड़ा, घइला, तरछी, डबुला दोहनी, मेटिया, ताई, नाद, दपकी,दिया, चुकड़ी, कलसा, तेलहड़ा, डबलुइया, करब,नगडिय़ा की कूड़, चिलम, हुक्का और गुल्लक।

काष्ठ: हल, जुआ, बैलगाड़ी, नाडी, खटिया, मचिया, मचबा, मचेड़ी, कोनइता की पारी, चकिया की पारी, चकरिया, चकिया के बेट, चौकी, पीढ़ा, ढोलकी के बारंग, बेलना, घर का छप्पर, तखत, कुआं की ढिकुरी, थामहा, केमार, दरवाजे का चउकठ, खूंटी, खुरपी का बेंट, कुदारी का बेंट, फरुहा का बेंट, कुल्हाड़ी का बेंट, हंसिया का बेंट, पाटी, बोड़की, परछी के खम्भे, पांचा, खरिया की कोइली, मोगरी, कठउता, कठउती, कुरुआ, पइला, कुरई, मूसल, ढेरा, कुरइली।

लौह: हंसिया, खुरपी, कुदारी, फरुहा, सबरी, सब्बल, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ा, कुंडा, ताला-चाबी, बसूला, रोखना, करछुली, चिमटा, डोल, कराही, हल की कुसिया, कील, कांटा, झंझरिया, छन्ना, तवा, गड़ास, गड़ासा, बरछी-भाला, तलवार, खुरपा, बल्लम, पासु, अमकटना, सरोता, बड़ा सरोत, पलउहा हंसिया, मूसल की साम, कजरउटा, अखइनी, रोखना, बसूला, रमदा, गिरमिट, रांपी, फरहा एवं परी।

पत्थर: लोढ़िया, कांडी, जेतबा, कुड़िया, चकिया, पथरी, लोढ़बा, चौकी, खल, होड़सा, कठौती।

धातः लोटा, थाली, कटोरा-कटोरी, बंटुआ, गिलास, हांडा, परात, भुजंगी, कलसा, तबेलिया, पीतल का लोटा, गंजा, पीतल की छोटी डोलची, घण्टी, कोपरी, पीकदान, कांसे का एक लैंप भी, फूलदान, पईना, पानदान, पील की बड़ी डोलची (डोंगा), फूल के खोरवा, बटलोह, पीतल के गघरा, पीतल के दौरी।

चमड़ा: बैल की घंटी व घुघ, जुएं में बैल के नधने के लिए जोतावर, बीज बोने के लिए ढोलिया की चर्म पट्टी, खेती से जुड़े कार्य हेतु लोहार की धौकनी, किसानों के केश कर्तक, नाई के छुरा की धार परताने के लिए चर्म पट्टिका, चर्म चरण पादुका, मसक, छोटे-छोटे बछड़े के गले में बांधने वाली ताबीज, चमौधी।

बाल से बनी सामग्री: मुस्का, गोफना, खरिया, रस्सी नारा, गेरमा, तरसा का रस्सा, भारकस, मोहरा, गडाइन, कांस की सुमडेरी।

महिलाओं द्वारा निर्मित: कुठला, कुठली, कुठुलिया, पेउला, गोरसी, सइरी।

रसायनिक उर्वरकों पर कम हुई निर्भरता

किसान कर रहे वर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल

भोपाल। जागत गांव हमार

सर्दियों के मौसम में भी जब बाहर अभी भी अंधेरा होता है, सोना पटेल का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है। जैसे ही वह उठती हैं, वह पशुशाला में जाती है जहां दो गाय, दो भैंस और चार बकरियां उनका इंतजार कर रहीं होती हैं। वो उन्हें खोलती है और फिर उन्हें खूटे पर वापस बांध देती हैं। रोजमर्रा के काम के बाद ही उनके दूसरे काम शुरू होते हैं। दूध के अलावा उन्हें पशुओं से गोबर भी मिलता है, जिससे वो वर्मी कम्पोस्ट बनाती हैं। सोना मध्य प्रदेश के धार जिले के बापदूद गांव की रहने वाली हैं।

सोना का कहना है कि मुझे पशुओं के गोबर को एक टोकरी में उस गड्ढे तक ले जाने में 15 मिनट लगते हैं, जहां हम खाद (वर्मीकम्पोस्ट) बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जैविक कचरे को डंप करते हैं। शेड में लौटने में 15 मिनट और लगते हैं। मैं ऐसे आठ बार आती-जाती हूं। जिनके पास 12 बीघा जमीन है। वर्मीकम्पोस्ट एक प्राकृतिक रूप से उत्पादित उर्वरक है जिसने पटेल परिवार की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर दी है। 2019 में, सोना पटेल और उनके पति रणछोड़, मनावर ब्लॉक के आठ गांवों के 73 अन्य किसानों के साथ ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। टीआरआईएफ ग्रामीण भारत में हाशिए के समुदायों के साथ काम करता है। प्रशिक्षण में एक वर्मीकम्पोस्ट इकाई के निर्माण पर सत्र शामिल थे जो उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के साथ-साथ उनके कृषि क्षेत्रों में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। किसानों को खाद बनाने और बाजार से केंचुए (वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए) प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया गया।

75 किसान बना रहे वर्मीकम्पोस्ट

अभी तक, मध्य प्रदेश में धार जिले के मनावर ब्लॉक में कुल 75 किसान वर्मीकम्पोस्ट बनाने में लगे हुए हैं, जिसका उपयोग उनके कृषि क्षेत्रों में उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे रासायनिक खाद खरीदने का उनका आर्थिक बोझ कम हुआ है और मिट्टी की सेहत में भी सुधार हुआ है। पटेल ने कहा कि वर्मीकम्पोस्ट बनाने में किए गए सभी प्रयास इसके लायक हैं, क्योंकि इससे मुझे एक साल में 12,000 रुपए से अधिक की बचत होती है, जो पहले डीएपी और यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों पर खर्च किए जाते थे।

किसानों को किया गया प्रशिक्षित

मनावर ब्लॉक के लिए टीआरआईएफ के कृषि समृद्धि कार्यकारी संजय भूरिया के अनुसार, किसानों को वर्मीकम्पोस्ट बनाने के लिए प्रशिक्षित करने का कल्याणकारी कार्यक्रम ग्रामीण कृषि अपशिष्ट का कुशल तरीके से उपयोग करने की तत्काल आवश्यकता को महसूस करने के बाद शुरू किया गया था। जब हम ग्राम पंचायत विकास योजना विकसित कर रहे थे, तो हमने देखा कि हमें गाय के गोबर और अन्य जैविक कचरे का उपयोग करने की जरूरत थी, जो सड़क के किनारे या खेतों में एक कोने में फेंक दिया जाता था। हमने सोचा कि उन्हें कैसे जोड़ा जाए। किसानों ने वर्मीकम्पोस्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कुछ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की जरूरत थी।

महिलाओं की अहम भूमिका

यह कार्यक्रम टीआरआईएफ, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और राज्य सरकार के बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। टीआरआईएफ ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता किया है ताकि परियोजना में महिलाओं को शामिल करने और उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए स्वयं सहायता समूहों जैसी सामाजिक संपत्तियों का उपयोग किया जा सके। भूरिया ने कहा कि नब्बे फीसदी कृषि श्रम महिलाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गोबर इकट्ठा करने से लेकर, इसे इकाइयों तक पहुंचाने, इसे पानी देने और खेतों में फैलाने तक, महिलाएं बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पांच वर्मीकम्पोस्ट बेड बनाए

ब्राह्मणपुरी गांव में 10-बीघा के मालिक सोहन चौहान ने अपने खेतों में पांच वर्मीकम्पोस्ट बेड बनाए हैं और हर तीन महीने में 15 क्विंटल वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन अपनी वर्मीकम्पोस्ट पद्धति के माध्यम से किया जाता है। जिससे उनकी खुद की जमीन के लिए 10 क्विंटल की बचत होती है और बाकी बची खाद 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देते हैं। एक वर्मीकम्पोस्ट बेड एटीएमए के लोगों द्वारा बनाया गया था, अन्य चार मैंने खुद से से बनाए थे। इसकी कीमत मुझे 5,000 रुपए प्रति बेड थी।

प्रशिक्षण के बाद शुरू हुआ काम

टीआरआईएफ द्वारा 2019 में परियोजना के तहत में 10 फीट × 3 फीट × 2.5 फीट आयामों की चार ठोस वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण करके शुरू किया गया था। बापदूद, दोंचा, बलीपुर और बिदपुरा के 50 किसानों को केंचुए भी दिए गए। हर दिन का काम किसान खुद से करते हैं और वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग पूरे क्षेत्र में फैलाने के बजाय फसल-लक्षित तरीके से किया जाता था। भूरिया ने बताया कि किसान अपने खेतों के लिए वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग करते हैं और फिर अतिरिक्त खाद बेचते हैं जिससे उनकी आर्थिक मदद हो जाती है। ब्राह्मणपुरी में, एटीएमए योजना के तहत दस इकाइयां विकसित की गईं, जिसमें जिला सरकार की मदद से हमारे शुरुआती प्रयास किए गए।

पौधों के लिए एक समृद्ध खाद

खाद बनाने की प्रक्रिया में 15 दिनों के बाद दो किलोग्राम केंचुओं को वर्मीकम्पोस्ट इकाई में गाय के गोबर और अन्य एकत्रित जैविक कचरे को डंप करना शामिल है जो अपघटन प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इस जमा कचरे में नमी के लिए 65-90 दिनों के दौरान पानी का छिड़काव करना पड़ता है। वर्मी-कास्टिंग युक्त पोषक तत्व पौधों के लिए एक समृद्ध खाद है। वर्मीकम्पोस्ट, पोषक तत्वों की आपूर्ति करने और पौधों को वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन के अलावा, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है जिससे मिट्टी की पानी और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। फल, फूल और सब्जियां और वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग करके उगाए गए अन्य पौधों के उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर रखने की सूचना है।

जल संकट एक बड़ी समस्या

पता चला कि एक बड़ी चुनौती जो उन्हें परेशान करती है, वह वर्मीकम्पोस्ट के गड्ढे में पानी की जरूरत है। प्रक्रिया के दौरान जिस नमी की मात्रा को लगातार बनाए रखने की जरूरत होती है, उसे 65-90 दिनों के दौरान दो-तीन दिनों में एक बार लगभग 15-20 लीटर पानी की जरूरत होती है। मानसून के दौरान स्थिति बेहतर होती है जब बारिश मांग को कम करने में मदद करती है। हालांकि हमारे खेत में एक कुआं है, हमारी खाद इकाई से बहुत दूर नहीं है, पाइप वहां तक नहीं पहुंचती है। हम कुएं से पानी ले जाने के लिए डब्बा का इस्तेमाल करते हैं और इसे हर इकाई में छिड़कते हैं। सोना एक चक्कर में 10 मिनट पानी लाने में लगाती है, और प्रतिदिन कुएं से इकाई तक लगभग आठ चक्कर लगाती है। टीआरआईएफ के अधिकारी भूरिया ने भी स्वीकार किया कि हालांकि केंद्र सरकार की हर-घर-नल योजना के तहत कई घरों में नल का कनेक्शन है, लेकिन वर्मीकम्पोस्ट के लिए पानी लाने में असुविधा बनी रहती है, जिसे दूर करने की जरूरत है।

अधिकांश गांवों में पर्याप्त भूजल

भूरिया का कहना है कि अधिकांश गांवों में पर्याप्त भूजल है और पानी के उपयोग से भूजल पर बोझ नहीं पड़ता है, लेकिन मनवर ब्लॉक के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से में अभी भी पानी की कमी है और यह चुनौतीपूर्ण है। वहीं धार के बागवानी विकास अधिकारी महिपाल बघेल ने बताया कि गर्मियों में, हमारे पास पानी की समस्या होती है, और केंचुए बिना नमी के जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए खाद का उत्पादन कम होता है। हम इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले भी वर्मीकम्पोस्ट योजना चला रहे थे, लेकिन कई लोग ये नहीं करना चाह रहे थे। हम किसानों को प्लास्टिक बेड, केंचुए और अन्य सहायता प्रदान करने में सहायता करते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत हो सकती है। केंचुओं का अन्य इकाइयों के लिए भी फिर ो उपयोग किया जा सकता है।

पानी खरीदना बड़ी चुनौती

सोनू ने भी शिकायत की कि कभी-कभी पानी की कमी के कारण वर्मीकम्पोस्ट के गड्ढे को बनाए रखने में खर्च बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार नमी की कमी के कारण केंचुए मर जाते हैं, क्योंकि पानी की आपूर्ति में समस्या आती है, तो किसान के लिए उन्हें 400 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से फिर से खरीदना एक चुनौती बन जाता है। किसानों को इन इकाइयों के निर्माण के लिए अपनी जमीन के उपलब्ध कराने के लिए राजी करना एक और चुनौती थी, लेकिन शुरुआती बाधा के बाद इसे दूर कर लिया गया। जिन किसानों को प्रशिक्षण सत्रों का बेहतर अनुभव था, उन्होंने इस पद्धति को अपनाया है।

लोगों को करना होगा जागरूक

वर्मीकम्पोस्ट बनाने और इस्तेमाल करने वाले 52 वर्षीय किसान परसाराम मालवीय बताते हैं कि वर्मीकम्पोस्ट के फायदों के बारे में किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ किसान आलसी होते हैं... उर्वरकों से वर्मीकम्पोस्ट की ओर पूरी तरह से निर्भर होना किसान समुदाय द्वारा जोखिम भरा माना जाता है। वे सोचते हैं कि यूरिया के उपयोग के बिना बीज ठीक से अंकुरित नहीं होगा। किसानों को समय-समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव है। यह अधिक किसानों को वर्मीकम्पोस्ट खाद अपनाने के लिए राजी करने में एक बाधा के रूप में काम कर रहा है।

जैविक खाद के बना रहे बैग

मालवीय वर्तमान में मौसम के आधार पर जैविक खाद के 350-500 बैग बनाते हैं। 50 किलोग्राम के प्रत्येक बैग- जिनमें से 100 का उपयोग उनके अपने खेतों में दो फसल चक्रों के लिए किया जाता है। बाकी बैग 350 रुपए प्रत्येक के लिए जो मुझे लगभग 100,000 रुपए की कमाई हो जाती है। खेतों के लिए मेरी लागत में भारी कमी आई है। पहले मैं साल में चार बोरी डीएपी और 15 बोरी यूरिया खरीदता था। वर्तमान में एक डीएपी बोरी की कीमत 1300 रुपए और यूरिया बोरी की कीमत 500 रुपए प्रति बोरी ब्लैक में बेची जा रही है।

बिगड़ती जैव विविधता बचाएंगे गौतम, अब तक लगाए 29.52 मिलियन पेड़

अडानी समूह लगाएगा 100 मिलियन पेड़

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है। इस खतरे को कम करने के लिए हर देश के उद्योगपति कुछ न कुछ पहल कर रहे हैं। इस दौरान दावोस में हो रहे विश्व आर्थिक मंच में अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि सीओपी-21 के द्वारा तय लक्ष्य 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन सिंक बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के तहत अडानी समूह आने वाले वर्ष 2030 तक 100 मिलियन पेड़ लगाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक अडानी समूह ने कई परियोजनाओं के तहत 29.52 मिलियन पेड़ लगाए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैंग्रोव के वृक्ष शामिल हैं। जो हमारे तटीय क्षेत्रों को स्थिर रखता है। हमारा 2030 तक 37.10 मिलियन और मैंग्रोव के पेड़ लगाने का लक्ष्य है।

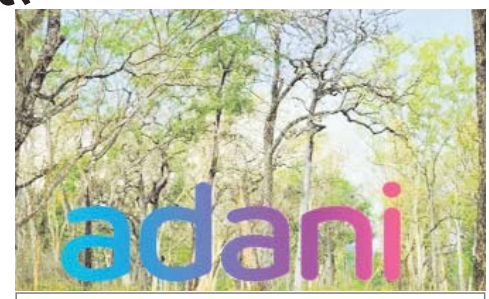

लक्ष्य जैव विविधता बचाना

कंपनी का लक्ष्य देश में हो रहे जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करना और बिगड़ती हुई जैव विविधता को रोकना है। हमारी संस्था कम कार्बन को कार्बन न्यूट्रल में बदलने में प्रयासरत है और धीरे-धीरे इसे हमको शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाना है। हमारी संस्था का लक्ष्य एग्रोफोरेस्ट्री, मैंग्रोव रिस्टोरेशन और अर्बन ट्री प्लानिंग के क्षेत्र में है। हमारी कंपनी कॉर्पोरेट एग्री सस्टेनेबिलिटी के साथ साझेदार है जो निकाय द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की निगरानी करेगी। इन तीन मुख्य लक्ष्यों के साथ-साथ नर्सरी और बीजों का विकास, वन प्रबंधन, शिक्षा, सामुदायिक गतिशीलता, डेटा संग्रह और प्रबंधन आदि में संस्था की भागेदारी रहेगी।

आईओटी सेंसर से रखी जाएगी निगरानी

मैंग्रोव और स्थलीय पेड़ों के नए पौधरोपण का लेखा -जोखा रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी के साथ-साथ आईओटी सेंसर के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। जिसकी कुल 282 साइटें 21 राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना , उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को चिन्हित किया गया है।

कीट नहीं कर पाएंगे हमला, मिलेगा बंपर उत्पादन

बैंगन की नई प्रजाति विकसित

भोपाल। देश के वैज्ञानिक लगातार कोशिश करते हैं कि हर फल, सब्जी की अच्छी से अच्छी प्रजाति विकसित की जाए। इसमें पानी की आवश्यकता कम हो। लागत कम लगे और उत्पादन अधिक हो जाए। इनका लाभ भी किसानों को मिलता है। अब बैंगन की ऐसी ही प्रजाति विकसित की है, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ जाएगा। किसानों के लिए यह प्रजाति खासी लाभकारी साबित होगी।

औरंगाबाद के जालना की कंपनी बेजो शीतल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड स्थित है। कंपनी ने जनक और बीएसएस 793 नामक पहली-फिलियल जनरेशन हाइब्रिड बैंगन की प्रजाति विकसित की है। इन प्रजातियों का लाभ आने वाले दिनों में किसान को मिलेगा। कंपनी के पदाधिकारियों का दावा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ट्रांसजेनिक तकनीक विकसितक की है। इस तकनीक की मदद लेकर ही बैंगन की नई प्रजाति जनक और बीएसएस-793 की बीटी किस्मों को विकसित किया गया है। इस प्रजाति में बीटी जीन, क्राय1 एफए1 जीन का प्रयोग किया है। इसे आईएआरआई ने पेंटेंट भी कराया है। इस तकनीक का प्रयोग करने से बेहतर गुणवत्ता की सब्जी, उपज हो सकेगी।

बीजों को नुकसान भी नहीं होता

बेजो शीतल ने तकनीक का लाइसेंस 2005 में ले लिया था। परीक्षण करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, बागलकोट, कर्नाटक से अनुरोध किया है। विशेष रूप से शूट और फ्रूट बोरर ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस जैसे कीटों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए विकसित किया गया है। इन प्रजातियों की अच्छी बात यह है कि बीजों का नुकसान प्रतिशत बहुत कम है। ऐसे समझ लिजिए, यदि 100 फल लेते हैं तो 97 बिना किसी नुकसान के विपणन योग्य हैं।

वैज्ञानिकों की देखरेख में होगा परीक्षण

यदि हाइब्रिड बैंगन किस्मों के परीक्षण का अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं तो कंपनी का अगला कदम इसका परीक्षण कराना होगा। इसके लिए कंपनी भारत में जैव प्रौद्योगिकी नियामक, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से संपर्क करेगी। यदि समय पर हमें गाइडलाइन मिल जाती हैं तो खरीफ सीजन में ही एक हेक्टेयर क्षेत्र में विश्वविद्यालय के स्तर से नामित वैज्ञानिक या फसल प्रजनक की देखरेख में परीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए यह भी देखना होगा कि कितने बीज की जरूरत पड़ेगी।

बंगाल की विशेष चिकनी मिट्टी से बन रही हैं देवी सरस्वती की प्रतिमाएं

भोपाल। राजधानी में वसंत पंचमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरस्वती पूजन के लिए शहर के कई सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तिकारों द्वारा विशेष प्रतिमाएं बनवाई जा रही हैं। शहरवासियों ने अपनी पंसद की देवी प्रतिमाएं बनवाने के लिए दो महीने पहले ही ऑडर दे दिए हैं। अब मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तिकार मोहनलाल प्रजापति ने बताया कि कोई वीणाधारी देवी बनवाते हैं तो कुछ कमल के सिंहासन पर विराजमान प्रतिमाएं बनवाते हैं। मूर्तियों में मां को भव्य रूप देने के लिए हंस, कमल, शंख, चक्र, रथ, वीणा, पुस्तक आदि के साथ बनाया जा रहा है। अब लोगों की नटराज मूर्ति और पहाड़ पर विराजमान देवी की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। देवी की प्रतिमाओं की स्थापना ज्यादातर सार्वजनिक स्थान, मंदिर और शैक्षणिक स्थानों में होती है। इसके साथ ही शहर के आसपास के कस्बों और छोटे शहरों से भी ऑर्डर आए हैं। इन मूर्तियों की कीमत एक हजार रुपए से 10 हजार तक रहेगी। सरस्वती देवी प्रतिमा के लिए साड़ी विशेष लाल, पीली और सफेद रंग की अलग-अलग डिजाइन में आ रही है। इसके साथ ही देवी प्रतिमा के लिए

दुधारू मालवी गाय और देसी उन्नत नस्ल की गायों को मिलेंगे पुरस्कार

आगर मालवा। जागत गांव हमार

कलेक्टर कैलाश वानखेड़े के निर्देशन में पशुपालन विभाग द्वारा जिले में मालवी गाय और भारतीय उन्नत नस्ल के जो वंशीय पशुओं के पालन को बढ़ावा देने और अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तरीय गोपाल पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन 13-14 फरवरी-2023 को पुराना पशु चिकित्सालय परिसर आगर में किया जा रहा है। उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं आगर डॉ. एचव्ही त्रिवेदी ने बताया कि यह योजना सभी वर्ग के पशु पालकों के लिए है, जिसके पास मालवी अथवा भारतीय उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध हो और मालवी गाय का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन कम से कम 04 लीटर या अधिक हो। भारतीय उन्नत नस्ल की गाय का दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन कम से कम 06 लीटर होने पर पंजीयन के लिए पात्र होंगे। प्रतियोगिता में पंजीकृत गाय के तीन समय के दुग्ध उत्पादन का औसत चयन का आधार होगा। पंजीकृत गायों में से सर्वाधिक दुग्ध देने वाली गाय का पुरस्कार दिया जाएगा।

तीन श्रेणी में पुरस्कार

इस वर्ष मालवी नस्ल की गाय की प्रतियोगिता और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण की व्यवस्था पृथक-पृथक होगी। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः 51 हजार, 21 हजार एवं 11 हजार का प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 02 लाख, द्वितीय पुरस्कार 01 लाख और तृतीय पुरस्कार 50 हजार रुपए प्रति गाय पर दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पशुपालकों को अपनी देसी एवं भारतीय नस्ल की दुधारू गायों के आवेदन नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था से प्राप्त कर 10 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं।

चंबल में स्वीकृत अटल प्रगति पथ के नए अलाइनमेंट में लगा ब्रेक

चंबल के 34 गांवों के किसानों की असहमति से अटक रहा सर्वे

मुरैना। जागत गांव हमार

चंबल में स्वीकृत अटल प्रगति पथ के नए अलाइनमेंट का सर्वे ग्रामीण व किसानों के विरोध के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। चंबल संभाग के तीनों जिले मुरैना, भिंड और श्योपुर में 15 दिसंबर तक सर्वे पूरा होना था। समय सीमा बीत जाने के बाद भी 34 से ज्यादा गांवों में ग्रामीण व किसानों के विरोध के कारण सर्वे अटका हुआ है। सर्वे पूरा होने के बाद ही जमीन अधिग्रहण व प्रोग्रेस-वे के ले आउट का काम आगे बढ़ेगा। गौरतलब है, कि अटल प्रगति पथ पहले चंबल नदी किनारे बीहड़ों में बनने वाला था, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति के बाद निरस्त कर दिया गया। अब नई प्लानिंग में इस एक्सप्रेस-वे को चंबल के बीहड़ों से तीन से चार किमी दूर बनाया जाएगा। एक्सप्रेस-वे चंबल संभाग के तीनों जिले मुरैना, श्योपुर और भिंड के 214 गांवों की निजी जमीन आ रही है। मुरैना जिले के 97 गांव, श्योपुर के 63 गांव और भिंड के 41 गांव हैं। इनमें से मुरैना जिले के 79 गांव में सर्वे पूरा हो गया, 18 गांवों में किसानों के विरोध के कारण सर्वे अटका हुआ है। इसी तरह भिंड के 10 और श्योपुर जिले के 6 गांवों में किसानों के विरोध व असहमति के कारण जमीन अधिग्रहण का सर्वे नहीं हो पा रहा है।

मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले के कुछ गांवों में विरोध के कारण सर्वे नहीं हो पा रहा। यह सरकार का प्रोजेक्ट है, इसलिए विरोध कर रहे किसानों को मनाएंगे, उन्हें इस प्रोजेक्ट से उनके गांव व पूरे अंचल को होने वाले फायदों से अवगत कराएंगे।
राजेश गुप्ता,प्रोजेक्ट इंचार्ज, एनएचएआई

इतने गांवों में सर्वे पूरा

तहसील	गांव	सर्वे पूरा
सबलगढ़	26	26
जौरा	28	18
मुरैना	12	06
अंबाह	10	08
पोरसा	21	21
कुल	97	79

एफएसएसएआई के सीईओ बोले-स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र

मोटा अनाज की खेती से बचेगा पानी और जेल में कैदियों की सुधरेगी सेहत

» अमिताभ ने कहा-किसान धान की जगह करें मोटे अनाज की खेती

» देश में मोटा अनाज मेला 100 शहरों में आयोजित किया जाएगा

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सीईओ कमला वर्धन राव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि जेलों में भी मोटा अनाज परोसा जाना चाहिए। राव ने कहा कि मोटा अनाज मेला 100 शहरों में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में भी हेल्थ क्लब शुरू करने की योजना बनाई है। वहीं भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि पानी की अधिक खपत को कम करने के लिए भारतीय किसानों को धान (चावल) की जगह मोटे अनाज की खेती की ओर जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान में केवल मोटा अनाज दिया जाना चाहिए। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि मोटा अनाज, पौष्टिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेष रूप से प्रोटीन से भरपूर होता है, और भारत में इसकी खपत को उच्च स्तर तक बढ़ाने की चुनौती है।

मोटे अनाज से बचेगा पानी

उन्होंने कहा कि भारत को चावल और गेहूं की खेती से अधिक से अधिक दूर जाने और अधिक से अधिक मोटा अनाज के उत्पादन एवं निर्यात की आवश्यकता है। मोटे अनाज की खेती से भी पानी बचाने में मदद मिलेगी। मोटे अनाज को भारत का सुपरफूड बनाने में निजी क्षेत्र को अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। सभी पोषण अभियान योजनाओं में केवल मोटे अनाज दिया जाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की तलाश

उन्होंने कहा कि हम अपने मोटे अनाज-आधारित उत्पादों को बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की भी तलाश कर रहे हैं। हाल ही में 5-6 भारतीय कंपनियों ने ब्रसेल्स में एक प्रदर्शनी में अपने मोटे अनाज-आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया।

मोटा अनाज पारंपरिक भोजन

अमिताभ कांत ने कहा कि वर्ष 2018 में केंद्र ने मिशन अभियान के तहत कुपोषण से लड़ने के लिए राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने तथा कार्रवाई करने के लिए अपना प्रमुख कार्यक्रम पोषण अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम में कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि मोटा अनाज भारत का पारंपरिक भोजन है और इसे बहुत कठिन क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है।

मोटे अनाज के उत्पादन पर जबलपुर कृषि विवि में होगी राष्ट्रीय कार्यशाला

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए जबलपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला होगी। कार्यशाला में किसानों के साथ विद्यार्थी, वैज्ञानिक, संस्थागत सदस्य, स्टार्टअप, स्वयं सेवी संस्थाएं, कृषि उत्पाद समूह और कृषि संबद्ध उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषकों का कार्यशाला में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अन्य प्रतिभागियों को निर्धारित शुल्क जमा कर 20 फरवरी तक पंजीयन कराना होगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और नाबार्ड द्वारा जो मोटे अनाज (मिलेट) का उत्पादन, प्र-संस्करण और विपणन-समस्या और समाधान विषय पर आगामी 1 और 2 मार्च को होगी।

सब्जी अनुसंधान संस्थान में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री

टमाटर की नई किस्म किसानों तक पहुंचाएं

भोपाल/वाराणसी। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा भाकृअनुप-भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी का गत दिनों दौरा किया गया। इस भ्रमण में केन्द्रीय मंत्री ने संस्थान के विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े चयनित गांव के किसानों से बातचीत की तथा संस्थान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। यहां किसानों ने संस्थान के द्वारा उनके गांवों में चलाए जा रहे परियोजनाओं तथा उनसे मिले बीजों, प्रशिक्षण, समय समय पर प्रक्षेत्र भ्रमण एवं संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा

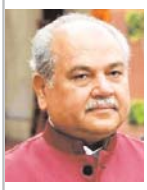

कृषि समस्यों का निदान से संतुष्टि जाहिर की तथा संस्थान से जुड़ने के बाद होने वाले लाभों के बारे में कृषि मंत्री को बताया। इसी क्रम में तोमर ने शोध क्षेत्र का भी भ्रमण किया। गाजर, टमाटर, मिर्च, मटर, जैविक और प्राकृतिक खेती, ग्राफ्टिंग व निक्रा में विकसित तकनीकों और गर्मी में उगाए जाने वाले टमाटर की किस्म काशी अद्भुत तथा ब्रिमाटो और पोमेटो की सराहना की। उन्होंने किसानों तक इन्हें जल्द से जल्द पहुंचाए जाने का भी कहा। तोमर ने एफपीओ से आए प्रतिनिधियों को संस्थान द्वारा विकसित तकनीकों के इस्तेमाल से अपने आय को गुणित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री ने संस्थान में पौधरोपण का भी कार्य किया। मशरूम यूनिट, मधुमक्खी इकाई, प्रसंस्करण इकाई इत्यादि का भ्रमण किया। संस्थान के निदेशक, डॉ. तुषार कांति बेहेरा ने सब्जी उत्पादन बढ़ाने में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी की भूमिका से रूबरू कराया। विगत 20 वर्षों में संस्थान के द्वारा 100 से अधिक किस्में एवं सब्जी उत्पादन की तकनीकें विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा किसानों के उत्पादों का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा मशरूम उत्पादन के प्रशिक्षण द्वारा उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास जारी है।

31 मार्च तक के लक्ष्य को जनवरी में पूरा किया

प्रधानंत्री स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश सरकार ने छह लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना से स्व-रोजगार, स्व-रोजगार से स्वावलंबन एवं स्वावलंबन से स्वाभिमान के पथ पर अग्रसर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य योजना में प्रथम और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में देश में प्रथम है। जिस लक्ष्य को 31 मार्च तक पूरा करना था उसे प्रदेश ने जनवरी में ही पूरा कर लिया। उक्त आशय की जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में दी। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तीनों चरणों में अभी तक सात लाख आठ हजार 255 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से छह लाख 47 हजार 951 हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

दूसरे चरण में इतने आवेदन मंजूर

योजना के द्वितीय चरण में बैंकों द्वारा एक लाख 57 हजार 158 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से एक लाख 23 हजार 261 आवेदकों को 20-20 हजार रुपये उनके बैंक खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। तृतीय चरण में बैंकों द्वारा पांच हजार 281 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से चार हजार 503 आवेदकों को 50-50 हजार रुपए ब्याज मुक्त ऋण उनके बैंक खातों में जमा करवा दी गई है। योजना में तीन चरणों में क्रमशः 10 हजार रुपए, 20 हजार और 50 हजार रुपए की ब्याज मुक्त कार्यशील ऋण पूंजी दी जा रही है। प्रदेश के पथ विक्रेताओं के मध्य डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लगभग तीन करोड़ 50 लाख का कैशबैक भी किया गया है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)